अमृत वाणी

नाव जल में रहे लेकिन जल नाव में नहीं रहना चाहिए इसी प्रकार साधक जग में रहे लेकिन जग साधक के मन में नहीं रहना चाहिए। **–रामकृष्ण परमहंस,**

प्रधानमंत्री की यथार्थ टिप्पणी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ चर्चा के दौरान पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए की गई यह टिप्पणी सर्वथा सही एवं उचित है कि दुनिया में आतंकी हमलों का एक ही केन्द्र है। भले ही प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर यह टिप्पणी की है फिर भी किसी भी देश के लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि आतंकवाद परस्त देश कौन सा है। यहां तक कि भले ही पाकिस्तान स्वीकार नहीं करे पर इस सच्चाई को वह स्वयं भी भलीभांति जानता है कि दुनिया भर में आतंकवाद को संरक्षण और सहयोग देने वाला देश वही है।

पाकिस्तान पर यह आरोप भले ही भारत ने लगाया हो पर दुनिया के अधिकतर देश यह मानते और कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहलाने वाला अमरीका भी इसका भुक्तभोगी है। यही वजह है कि अमरीका ने कई बार उसे सख्त चेतावनी देते हुए उसे दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी रोक लगा रखी है।

जहां तक भारत का सवाल है तो भारत अपने इस पड़ोसी देश के कारण दशकों से आतंकवाद का दंश सह रहा है। कहने को तो, भारत अगर चाहे तो अपनी ताकत से बड़ी आसानी से इसका खात्मा कर सकता है लेकिन एक शांतिप्रिय देश होने के नाते यही प्रयास करता आ रहा है कि बातचीत के द्वारा यह मसला सुलझा लिया जाय। पिछले कई दशकों में पाकिस्तान में कितने ही शासक आए और गए। प्रत्येक के साथ भारत ने भरसक कोशिश की लेकिन सभी एक ही थाली के चट्टे-बट्टे निकले। वस्तुतः पाकिस्तान की नीयत कभी भी साफ नहीं रही। हमेशा दोहरा चेहरा अपनाकर अपनी स्वार्थ सिद्धकर लेना उसका लक्ष्य रहा है। उसका यह मंसूबा रहा है कि एक ओर वो दुनिया के सामने भला बनने भारत के साथ वार्ता की मेज पर बैठे और दूसरी ओर पीछे से अपनी आतंकवादी गतिविधियां बदस्तूर जारी रखे। इसकी अनुमति तो उसे दी नहीं जा सकती। अतः भारत न स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से वार्ता तभी होगी जब वह आतंकवाद का साथ छोड़ेगा।

दरअसल पाकिस्तान अब स्वयं ही फंस गया है। जिन आतंकवादियों को उसने अब तक सहारा और संरक्षण दिया वे अब उस पर इस कदर हाबी हो गए है कि उनके इच्छा के विरूद्ध कार्य करना या उन्हें दूर करना अब उसके बस की बात नहीं है। यही वजह है कि अपने देश में हो रहे भारी आतंकवादी हिंसा के सामने भी वो मजबूर हो।

अतः यही कहा जा सकता है कि जो पौधा उसने बोया है उसी को अब उसे काटना पड़ रहा है। बल्कि अब वो दोहरी मार का शिकार है। एक अपने ही देश में और दूसरा दूसरे देशों से। कहते हैं न कि जैसी करनी वैसा फल।

राज काज

अटकलें ही अटकलें हकीकत कहां

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और केंद्र सरकार के बीच संघर्ष की खबरें अब अटकलों में तब्दील हो चुकी हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि बैंक और सरकार के बीच सब कुछ सही हो गया है और अब आरबीआई गवर्नर के द्वारा पद से इस्तीफा देने की अटकलें भी खत्म हो गई हैं। इस आशय की खबर आने के साथ ही जानकारों ने कहना शुरु कर दिया है कि उर्जित मोदी सरकार के पहली पसंद थे, ऐसे में सरकार और गवर्नर के बीच किसी संघर्ष की बात सिरे से गलत प्रतीत होती है। यह पूरा मामला दरअसल पहले सूत्रों द्वारा मीडिया को भ्रमित करते हुए अनावश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना रहा है और उसके बाद अफवाहें और अटकलें बताकर असली मामले से लोगों का ध्यान भटकाना रहा है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ पहले ही कह चुके हैं कि सरकार के गलत फैसलों का आंकलन पूर्व गवर्नर ने जो किया था वही सही है वाकी लोग तो लीपा.पोती में लगे हुए हैं। इसलिए अटकलों और अफवाहों को जगह मिलती रही है।

अच्छे नहीं लगे सफाई देते आफरीदी

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने इंग्लैंड की संसद कही जाने वाली हाउस ऑफकॉमन्स में पहले कहा कि पाकिस्तानी सरकार और सेना को कश्मीर की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनसे अपने चार प्रांत भी संभाले नहीं जा रहे हैं। संभवतरू इसके बाद पाकिस्तान में उनका विरोध खासतौर पर हुआ होगा इसलिए अब शाहिद ने अपने बयान से पलटी मारते हुए कहना शुरु कर दिया है कि कश्मीर में भारत जुल्म ढा रहा है। इसी के साथ उन्होंने यहां तक कह दिया कि कश्मीर पर दिए गए उनके बयान को सही तरीके से पेश नहीं किया गया, इसलिए यह स्थिति बनी है। शाहिद ने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई पेश की है, जिससे समझा जा सकता है कि उन्होंने जो पहले कहा वह ही सच्चाई थी और अब अपने विरोधियों को संतुष्ट करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आफरीदी ही क्या ज्यादातर विचारकों ने तो यही बात अलग अंदाज में कही, लेकिन पाकिस्तान का निजाम आंखें दिखाने वाला रहा है इसलिए अब आफरीदी भी सफाई देते अच्छे नहीं लग रहे हैं।

आरक्षित सीटों पर है जीत का दारोमदार

नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले चरण में विधानसभा की कुल 90 में से 18 सीटों पर हुए चुनाव में जिस प्रकार जनता जनार्दन ने नक्सलियों की धमकियों से बेपरवाह होकर 70 फीसदी मतदान कियाए उसके लिए वहां की जनता निसंदेह बधाई की पात्र है। 18 सीटों पर मतदान के बाद अब 20 नवम्बर को शेष 72 सीटों पर मतदान होना है और पहले चरण के मतदान के बाद इन सीटों के लिए घमासान अब और तेज हो गया है। प्रदेश में कुल 2ण्55 करोड़ मतदाता है और दिलचस्प बात यह है कि महिला मतदाताओं की संख्या भी यहां पुरूषों के लगभग बराबर है तथा करीब डेढ़ दर्जन सीटों पर तो हार.जीत का सारा दारोमदार महिला मतदाताओं पर ही होता है। 90 में से 10 सीटें अनुसूचित जाति, 29 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं जबकि 51 सामान्य सीटें हैं लेकिन इन सामान्य सीटों में से भी करीब 11 सीटों पर अनुसूचित जातियों का काफी प्रभाव देखा जाता है।

छत्तीसगढ़ में करीब 1.1 करोड़ मतदाता एस.एसटी समुदाय से हैं और इन्हीं सब परिस्थितियों के आधार पर सभी पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखते हुए जातीय समीकरण साधने की कवायद कर रही हैं क्योंकि इस राज्य में आरक्षित सीटें सत्ता की अहम केन्द्रबिन्दु रही हैं, जिनकी अनदेखी कर सत्ता की वैतरणी पार कर पाना नामुमकिन है। हकीकत यही है कि आरक्षित सीटों में से सर्वाधिक सीटें जीतने वाला दल ही यहां सदैव किंगमेकर की भूमिका में रहा है। यही वजह है कि जहां भाजपा को इस राज्य में पिछड़ी जातियों के बीच भी लोकप्रिय माना जाता रहा है, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करते हुए पिछड़ी जातियों से संबंध रखने वाले कई नेताओं को खास अहमियत देकर कुछ अहम पदों पर उनकी नियुक्तियां की हैं। प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बघेल कुर्मी समुदाय से हैं जबकि राज्य के प्रभारी महासचिव पी एल पुनिया अनुसूचित जाति से और राज्य प्रभारी चंदन यादव पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। पिछली जाति के पूर्व केन्द्रीय मंत्री चरणदास महंत और सांसद ताम्रध्वज साहू को भी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है।

2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को आरक्षित सीटों में 24 जबकि कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी और 2013 के चुनाव में भाजपा को 20 जबकि कांग्रेस को 19 सीटों पर सफलता मिली थी। कुछ विश्लेषक अब मान भी रहे हैं कि एससी.एसटी वोट बैंक अब धीरे.धीरे भाजपा से छिटक रहा है और कांग्रेस इनके बीच अपना जनाधार मजबूत करती जा रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 25 फीसदी से कम एसटी आबादी वाली सीटों पर भाजपा को लाभ मिलता रहा है किन्तु 50 फीसदी से अधिक एसटी आबादी वाली सीटों पर कांग्रेस का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। 2003 में भाजपा को 41.4 फीसदी एसटी वोट मिले थे जबकि कांग्रेस को महज 34ण्9 फीसदी, 2008 में भाजपा को 39.2 फीसदी और कांग्रेस को 36.5 फीसदी लेकिन 2013 में भाजपा को 38ण्6 और कांग्रेस को 41.6 फीसदी वोट प्राप्त हुए थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि कभी भाजपा की मजबूती का आधार रही आरक्षित सीटों पर कांग्रेस की बढ़त का अगर यही रूझान बरकरार रहा तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।

2003 से 2013 तक के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो 2003 में भाजपा को 39.26 फीसदी मतों के साथ 50 सीटें जबकि कांग्रेस को 36.71 फीसदी मतों के साथ 37 सीटें प्राप्त हुई थी। एनसीपी को 7.02 और बसपा को 4.45 फीसदी मत मिले थे। 2008 में भाजपा 40.33 फीसदी मतों के साथ 50 सीटें जीतने में सफल हुई थी जबकि कांग्रेस को 38.63 फीसदी मतों के साथ 38 सीटें मिली थी। बसपा ने 6.11 फीसदी मत प्राप्त किए थे। 2013 के चुनाव में भाजपा को 41.04 फीसदी मतों के साथ 49 सीटों पर सफलता मिली और कांग्रेस को 40.29 फीसदी मतों के साथ 38 सीटों से संतोष करना पड़ा। बसपा 4.27 फीसदी मतों के साथ एक सीट जीतने में सफल हुई थी।

वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए इस आदिवासी बहुल राज्य में पहली सरकार अजीत जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस की बनी थी किन्तु 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली थी और 7 दिसम्बर 2003 से यहां डा. रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा सत्तारूढ़ है लेकिन भाजपा के शासनकाल के इन डेढ़ दशकों में कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जो जस की तस हैं और लोगों में उन्हें लेकर खूब नाराजगी है। सत्ता विरोधी लहर का सामना भी भाजपा को करना पड़ रहा है। भले ही प्रदेश में विकास कार्यों का खूब ढ़िंढ़ोरा पीटा जाता रहा हो किन्तु वास्तविकता यही है कि राज्य के कई इलाके ऐसे हैं, जहां विकास कार्यों को बड़े स्तर पर अनदेखी हुई है, जिसे लेकर जनता का आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। कई इलाके नक्सल प्रभावित हैं, जहां बहुत कम विकास हुआ है और ऐसे इलाकों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की भारी कमी है। इस राज्य के किसानों की कृषि से आय भारत में सबसे कम है, इसलिए किसानों में भी आक्रोश है। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा नक्सलवाद पर नकेल कसने में सफल नहीं हो सकी बल्कि यह समस्या और बढ़ी है। राज्य के कई हिस्से नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं और आंकड़ों पर नजर डालें तो 2005 से अभी तक तीन हजार से अधिक लोग नक्सली हिंसा की भेंट चुके हैं। कांग्रेस की एक पूरी परिपक्व पीढ़ी ही कुछ बरसों पहले नक्सली हिंसा की भेंट चढ़ चुकी है, जिसका खामियाजा उसे अभी तक भुगतना पड़ रहा है।

मुख्य चुनावी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है और दोनों ही दलों द्वारा नवम्बर के दूसरे सप्ताह में जारी अपने.अपने घोषणा पत्र में सभी वर्गों को लुभाने के लिए ढ़ेर सारे दावे और वायदे किए गए हैं। एक ओर जहां भाजपा ने गरीबों के लिए पक्के मकान, गरीबों को पांच लाख का बीमा, 60 साल से अधिक आयु के भूमिहीन किसानों व खेतीहर मजदूरों को 1000 रुपये पेंशन, युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौशल उन्नयन भत्ता, दलहन.तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने जैसे वायदे किए हैं, वहीं कांग्रेस ने सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने और दो साल का बोनस दिए जाने, ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए पक्के मकान, प्रत्येक परिवार को एक रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 35 किलो चावल, 60 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन योजनाए घर.घर रोजगार, हर घर रोजगार के तहत युवाओं को नौकरी, राजीव मित्र योजना के तहत 10 लाख बेरोजगारों को मासिक भत्ता दिए जाने जैसे वायदे अपने घोषणापत्र में किए हैं।

हालांकि भाजपा को यहां डेढ़ दशकों के दौरान किए अपने कामकाज और केन्द्र की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जीत का भरोसा है और प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार प्रचार से भी पार्टी की उम्मीदें बढ़ी हैं लेकिन टिकटों से वंचित रह गए कई दिग्गज नेता पार्टी का खेल बिगाड़ने में भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिलने की कुछ उम्मीदें तो हैं ही और संकल्प यात्रा के जरिये राहुल गांधी जिस प्रकार प्रचार को धार दे रहे हैं, वह भी कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है लेकिन पार्टी के भीतर व्याप्त गुटबाजी कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। कांग्रेस के लिए दुविधा यह भी है कि अजीत जोगी के कांग्रेस से अलग होने के बाद राज्य में उसके पास कोई करिश्माई नेता नहीं है।

हालांकि अधिकांश सर्वेक्षणों में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है लेकिन प्रदेश में अजीत जोगी की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने जातीय समीकरण साधने के लिए अपनी नई पार्टी ष्जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का बसपा और भाकपा के साथ गठजोड़ कर कांग्रेस के साथ.साथ भाजपा के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बसपा भले ही यहां कोई दमदार भूमिका में नहीं है किन्तु कुछ सीटों पर समीकरण बिगाड़ने में अहम भूमिका अवश्य निभा सकती है। पिछले चुनाव में उसे 4.27 फीसदी मत मिले थे। राज्य में सतनामी समुदाय की करीब 12 फीसदी आबादी है और अजीत जोगी की प्रदेश में एसटी के अलावा सतनामी समुदाय पर भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बहरहाल, देखना यह है कि एससी.एसटी और पिछड़ा वोटबैंक किस दल का खेवनहार बनकर उसे सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचाने में मददगार साबित होता है।

योगेश कुमार गोयल
(ये लेखक के अपने विचार है)

राममंदिर बनाम राजनीति

इन दिनों जब पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और लोकसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। तब कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आगामी चुनावों में भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए अयोध्या में राममंदिर निर्माण के मुद्दे को हवा दे रही है। उनका यह भी आरोप है कि मोदी सरकार को पिछले साढ़े चार साल में मंदिर निर्माण का मुद्दा याद नहीं आया।

वस्तुतरू इस मुद्दे ने जोर तब पकड़ाए जब दिल्ली के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार से कहा कि वह कानून बना कर राम मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करे। लोगों को यह भी पता होगा कि 29 अक्टूबर से सर्वोच्च न्यायालय में राममंदिर के मुद्दे पर सुनवाई होनी थी, जिसमें जन भावना यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे को रोजाना सुनवाई कर प्राथमिकता के साथ निपटाएगा। पर लागों को तब भारी निराशा हुई जब सर्वेच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई शुरू होते ही बगैर किसी कारण के राममंदिर या राम जन्मभूमि पर सुनवाई को जनवरी 2019 तक कि लिए स्थिगित कर दिया। विडम्बना यह कि एक तरफ तो विरोधी दल भाजपा पर यह आरोप लगाते हैं कि ये आए दिन राममंदिर बनाने की बातें तो करते हैं पर तारीख नहीं बताते। अब जब ऐसा माना जाने लगा है कि मोदी सरकार संसद में विधेयक या अध्यादेश लाकर अयोध्या में राममंदिर निर्माण का मार्ग प्रश्स्त कर सकती है, तब उसकी संभावना मात्र से विरोधी दलों के पेट में दर्द होने लगा है। एक तरफ तो वह कहते हैं कि हम राममंदिर निर्माण के विरोधी नहीं हैं। यहां तक कि राहुल गांधी को बतौर रामभक्त एवं शिवभक्त प्रचारित किया गया। पर जैसे ही राममंदिर निर्माण की दिशा में कुछ ठोस बातें चलती हैं, तो यही कांग्रेस पार्टी और अन्य विरोधी पार्टियां प्रकारांतर से इसके विरोध पर उतारू हो जाती हैं। वह जानते हैं कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, फिर भी संघ, भाजपा एवं विहिप से कुछ ऐसे तारीख जानने की अपेक्षा करते हैं कि वे तारीख बताए तो हम भी प्राणप्रण से राममंदिर निर्माण में भागीदारी निभाएं। जब कि उनका मकसद मात्र इतना रहता है कि वह यह साबित कर सकें कि भाजपा स्वतरू मंदिर मुद्दे पर गंभीर नहीं है और वोट लेने के लिए इसे मुद्दा बनाए हुए है। पर दूसरी तरफ वह यह भी कहते हैं कि जब राममंदिर का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो इस पर सरकार कोई फैसला कैसे ले सकती हैघ् जबकि पूर्व जस्टिस चेमलेश्वर का कहना है कि सरकार द्वारा राममंदिर निर्माण में पहल किये जाने में कोई बाधा नहीं है।

हकीकत यह कि राममंदिर निर्माण पर यदि कोई फैसला लिया जाएगा तो वह देश की संसद लेगी और जिसे इस बात का पूरा अधिकार है। आखिर में इस मामले में जो लोग यह कहते हैं कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उनके पास इस बात का क्या जवाब है कि राजीव गांधी की सरकार के समय मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने को लेकर ष्शाहबानो प्रकरणष् में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कैसे संसद द्वारा उलट दिया गया था। जबकि राममंदिर के मामले में अभी तक कोई फैसला आया नहीं है, और यदि सरकार को इस दिशा में कोई निर्णय लेना पड़ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में फैसला देने में आवश्यक तत्परता नहीं बरत रहा है।

जहां तक आरोप यह है कि यह मुद्दा पिछले साढ़े चार साल तक याद क्यों नहीं आया। तो इस बात में कोई दम नहीं है। अलबत्ता कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि उसके एक नेताध्वकील कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में यह क्यों कहा था कि राममंदिर निर्माण की सुनवाई अगले लोकसभा चुनाव तक के लिए टाल देनी चाहिए। निश्चित रूप से साढ़े चार वर्ष तक राममंदिर निर्माण की पक्षधर ताकतें इस बात का इंतजार करती रही कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अपना फैसला सुनाए। पर जब अब मामला अनिश्चित काल के लिए लटक सकता है तो इसमें लोगों की व्यग्रता समझ में आती है। क्योंकि राम हमारे राष्ट्र के प्रतीक और संस्कृति की पहचान हैं। महात्मा गांधी ने स्वतरू कहा था कि मुसलमान भी राम को एक महापुरूष मानकर सम्मान दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह अवश्य कहा जा सकता है कि राममंदिर के मुद्दे पर राजनीति कांगेस एवं अन्य विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। अलबत्ता इतना जरूर है कि कभी राम जन्मभूमि में पुनरू मस्जिद बनाने की बात करने वाले और राम जन्मभूमि के मुद्दे को विशुद्ध साम्प्रदायिक और मुस्लिम विरोधी बताने वाले अपने घटते जनाधार के चलते सुर बदलने को बाध्य हैं, और हिन्दू मतों के चक्कर में राम नाम जप रहे हैं। पर मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने के चक्कर में इनकी स्थिति मुंह में राम बगल में छुरीष् वाली है। तभी तो ऐसे लोग राममंदिर का प्रश्न आते ही कहीं रंच.मात्र समर्थन करना तो दूर येन.केन.प्रकारेण तरह.तरह के कुतर्को पर आमादा हो जाते हैं।

उम्मीद है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार राममंदिर निर्माण की दिशा में संसद में विधेयक लाकर अथवा ऐसा संभव न होने पर अध्यादेश लाकर तेजी से कदम उठाकर राममंदिर निर्माण की दिशा में जन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेगी। तब यह साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा रामभक्त है और कौन रामविरोधी।

वीरेन्द्र सिंह परिहार
(ये लेखक के अपने विचार है)

नरभक्षी वन्य प्राणी को मारे जाने पर मेनका का मर्सिया

महाराष्ट्र में जहाँ 13 लोगों को मारने वाली नरभक्षी बाघिन को मारे जाने पर केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी मर्सिया पढ़ रही हैं और वहाँ के वन मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें हटाने की मांग कर रही हैं, वहीं गुजरात में भाजपा नेता, राज्य के पूर्व मंत्री जंगली प्राणियों को मारने की छूट देने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अमरेली जिले के खडाधार में एक शेरनी ने बकरी का शिकार करने का प्रयास किया था।

उस दौरान वहां मौजूद बकरी के मालिक ने बकरी को बचाने के लिए शेरनी पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। इस मामले में बकरी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल में बंद बकरी के मालिक से मिलने भाजपा नेता दिलीप संघाणी जेल पहुंच गए और शेरनी पर हमला करने के लिए उसकी पीठ थपथपा दी।

आरोपी का बचाव करते हुए दिलीप संघाणी कह रहे हैं कि जंगली प्राणी जब इंसान पर हमला करेंए उस वक्त जंगली प्राणी को मारने की छूट दी जानी चाहिए। संघाणी का कहना है कि इंसान को अपनी जान बचाने के लिए इंसान तक की जान लेने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में जंगली प्राणी से जान बचाने के लिए एक इंसान को जेल में बंद कर देना उचित नहीं है। उन्होंने ऐसे कानून में सुधार करने की वन विभाग और सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अतीत में शेर से लडने् वालों का सम्मान किया जाता था और इसलिए शेरनी पर हमला करनेवाले बकरी मालिक का भविष्य में सम्मान करेंगे। सरकार शेर सुरक्षित होने का दावा कर रही है।

जहाँ तक महाराष्ट्र में बाघिन अवनि को मारे जाने के बाद बवाल बढ़ा तो वन मंत्री सुधीर मुंगतिवार ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फड्णवीस और पार्टी अध्यक्ष कहेंगे तो वह इस्तीफा दे देंगे लेकिन यह तय करने का हक मेनका गांधी को नहीं है। सुधीर ने मेनका गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहाए श्मेनका जी मेरा इस्तीफा मांगने की बजाय कुपोषण और बच्चों की मौत रोकने के लिए काम करें। मैं भी मानता हूं कि टाइगर्स का जीवन महत्वपूर्ण है लेकिन मेरा यह भी मानना है कि मानव जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता कि यह उन्हें क्यों समझ नहीं आ रहा।

हमारा मानना है कि वन्य प्राणियों का संरक्षण होना चाहिए। लेकिन यदि कोई प्राणी किसी मनुष्य के जीवन के लिए घातक हो जाए तो उसे मारा ही जाना चाहिए। अगर अवनि ने मेनका पर ही हमला किया होता तो क्या वे तब भी ऐसा ही मर्सिया पढ़तीं।

अजित वर्मा
(ये लेखक के अपने विचार है)